नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 देश में बाढ़-बारिश से स्थिति विकराल

4 अब ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का क्या होगा?

9 एफसीएनआर जमा ने बनाया नया रिकॉर्ड

11 ईशा सिंह ने जीता स्वर्ण, मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक

पेपर लीक संशोधन बिल पेश

विपक्ष के हंगामे के कारण लोस की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नयी दिल्ली, 27 जुलाई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया. विधेयक पेश किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद सदन में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई..

वहीं इस विधेयक के तहत दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है. इनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, दोषियों की संपत्ति जब्त करना और मामलों का फैसला तीन महीने के भीतर सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है. वहीं, राज्यों को केन्द्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की रिपोर्ट मांगी.

तीन बार स्थगन के बाद पांच बजे कार्यवाही शुरू की तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे. श्री तेन्नेटी ने सदस्यों से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और लाठीचार्ज के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया. उन्होंने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया. इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयक होने के बावजूद कांग्रेस जानबूझकर अवरोध उत्पन्न कर रही है. उन्होंने कहा कि सभी को इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए. स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सदस्यों से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा प्रारंभ करने का आग्रह किया लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस तथा अन्य कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आ गये और तख्तियां लहराते हुए पेपर चोर के नारे लगाने लगे. वहीं बीजेपी के सांसदों ने जिन्दा बाद के नारे लगाए. वहीं, बाद में पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने कहा कि यह विधेयक देश के युवाओं के भविष्य के लिए है. उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते हैं इस विधेयक पर चर्चा हो. युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. वहीं पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही चौथी बार शाम सवा पांच बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म

संसद में सरकार और विपक्ष के बीच का गतिरोध खत्म हो गया है, जिसके बाद एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा और लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर सहमति बन गई है .संसद में बनी यह सहमति लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल और सभी दलों के साथ हुई बैठकों का परिणाम है। मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से संवाद कर गतिरोध को दूर किया।वहीं वोटिंग भी संभव हो सकती है.

रोजाना सुनवाई का प्रावधान क्या

- परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ पहले से कहीं कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.
- दोषियों के लिए सजा और आर्थिक दंड दोनों बढ़ाए जाएंगे ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का अधिकार मिलेगा
- यह कानून केंद्र सरकार तथा उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू रहेगा

प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं रुकी तो होगा प्रदर्शन : सीजेपी

नयी दिल्ली, 27 जुलाई. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनकारियों तथा छात्र कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सीजेपी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक बयान में कहा है कि यदि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के अपने आश्वासन का पालन नहीं किया तो पार्टी दोबारा आंदोलन करेंगे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम देख रहे हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली और अन्य राज्यों में सैकड़ों छात्रों की निगरानी की जा रही है तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है. दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रसद सहायता पहुंचाने वाले लोगों को भी हिरासत में लिये जाने की रिपोर्टें सामने आ रही हैं.

मीराबाई ने वेटलिफ्टिंग में लगातार तीसरी बार CWG गोल्ड मेडल जीता!

82 लाख किसानों के खातों में भेजे 3300 करोड़

किसानों को दिन में मिलेगी पर्याप्त बिजली : सीएम डॉ. मोहन यादव

खंडवा, 27 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है जिससे किसानों को सिंचाई के लिए रात की जगह दिन में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके.

उन्होंने कहा कि रात के समय किसानों को करंट लगने, जहरीले जानवर आदि के काटने का डर रहा है. इसे लेकर सरकार चिंतित है. सांदीपनि आश्रम की तर्ज पर राज्य में आधुनिक सुविधाओं वाले सांदीपनि विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं. साथ ही ओंकारेश्वर, महाकाल व दादा धूनीवाले धाम सहित प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सत्ता में आने से पहले पूरे प्रदेश में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया है.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को खंडवा में बलराम कृषि महोत्सव के उद्घाटन पर संबोधित किया. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और तीन तलाक को लेकर साफ शब्दों में कहा कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राम की एक तो रहीम की चार कैसे? महिलाओं के सम्मान के लिए तीन तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म करना बेहद जरूरी था, जिसका बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी समर्थन किया है. उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण और समाज में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया. डॉ. यादव ने प्रदेश के 82 लाख किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से किसान सम्मान निधि के 3300 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए.

एक नजर में

पंजाब में बीजेपी ऑफिस पर पेट्रोल बम से हमला

चंडीगढ़. पंजाब के संगरूर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को निशाना बनाकर कथित रूप से पेट्रोल बम से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना रविवार तड़के करीब 3 बजे की बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर बीजेपी कार्यालय की ओर फेंकी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और आग लग गई. कार्यालय की बाहरी दीवारों पर काले धब्बे दिखाई दिए. हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और कार्यालय में मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

राजकोट. दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को सोमवार दोपहर गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. उड़ान के दौरान पायलट ने विमान के कार्गो होल्ड एरिया में संदिग्ध धुआं देखा, जिसके बाद बिना समय गंवाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्थिति की जानकारी दी और नजदीकी सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति मांगी. राजकोट एयरपोर्ट को तुरंत हाई अलर्ट पर रखा गया और सभी आपातकालीन सेवाएं रनवे पर तैनात कर दी गईं.

गुस्ताखी माफ

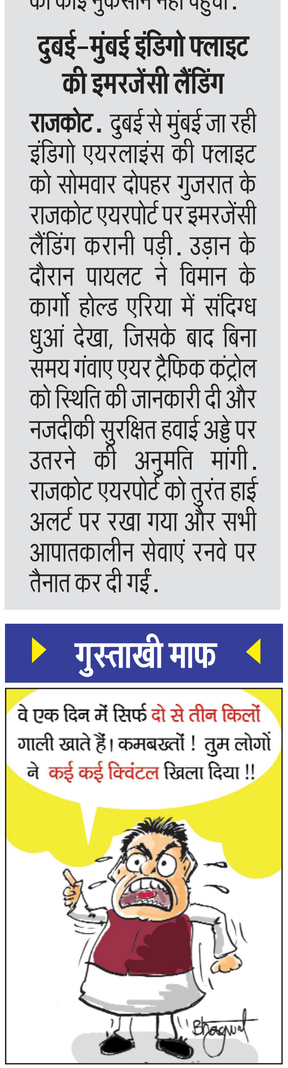

10 और 20 के प्लास्टिक नोटों को मंजूरी

- आरबीआई करेगा 100-100 करोड़ पॉलीमर नोटों का ट्रायल
- भविष्य में सफल होने पर लिया जाएगा चलाने का निर्णय

नई दिल्ली, 27 जुलाई. भारतीय करेंसी में तकनीकी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 10 और 20 के पॉलीमर बैंक नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है.

संसद में वित्त मंत्रालय ने बताया कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर दोनों मूल्यवर्ग के 100-100 करोड़ पॉलीमर नोट जारी कर उनके वास्तविक उपयोग, टिकाऊपन और प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा. इस ट्रायल के परिणामों के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि भविष्य में इन नोटों को नियमित रूप से जारी किया जाए या नहीं. भारत में भी छोटे मूल्यवर्ग के नोट सबसे अधिक प्रचलन में रहते हैं और लगातार उपयोग के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में 10 और 20 के नोटों से इस नई तकनीक की शुरुआत की जा रही है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पॉलीमर नोट आने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागज के नोट तुरंत बंद कर दिए जाएंगे. दोनों प्रकार के नोट एक साथ प्रचलन में रहेंगे और आम लोगों को पुराने नोट बदलने या किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

> पॉलीमर नोट सामान्य कागज के नोटों की तुलना में अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं. ये पानी, नमी, धूल और गंदगी से जल्दी खराब नहीं होते तथा आसानी से फटते भी नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि पॉलीमर नोटों का जीवनकाल कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक होता है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने पहले ही इस तकनीक को अपनाया है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस ही रहेंगे लागू

नई दिल्ली, 27 जुलाई. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने संसद में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है. सरकार के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा समय में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगी.

गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक!

12 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 11 संदेश में मौजूद थे

20 को यूनिवर्सिटी ने जांच दल को दी थी जिम्मेदारी

जूनागढ़, 27 जुलाई. गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. तीसरे वर्ष की परीक्षा के सर्जरी विषय के प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है.

प्रश्नपत्र और वायरल संदेश में समानता मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शल्य तंत्र-1 विषय की परीक्षा से पहले व्हाट्सऐप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा संदेश तेजी से प्रसारित हुआ था. परीक्षा समाप्त होने के बाद जब इन वायरल प्रश्नों का वास्तविक प्रश्नपत्र से मिलान किया गया तो दोनों में काफी समानता पाई गई. बताया जा रहा है कि प्रश्नपत्र में कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 11 प्रश्न वायरल संदेश में मौजूद थे.मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आंतरिक स्तर पर पड़ताल शुरू की है. जूनागढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी जांच दल के सदस्य डॉ. अल्पेश जरसानिया ने बताया कि 20 जुलाई को उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से जांच दल की जिम्मेदारी दी गई थी. जब वह कॉलेज में जांच के लिए पहुंचे तो एक शिक्षक ने उन्हें व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहे प्रश्नों की जानकारी दी.

एयर इंडिया और सरकार में साझेदारी

इन्क्रेडिबल इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली, 27 जुलाई। भारत को विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।

इस करार के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर भारत को वैश्विक पर्यटन और विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए संयुक्त रणनीति पर काम करेंगी। समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, देश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन अनुभवों को वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही भारत को एक प्रमुख वैश्विक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी सहयोग किया जाएगा।

ई20 विवाद : गडकरी ने दायर किया मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली, 27 जुलाई. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 एथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार और डीपफेक वीडियो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. कोर्ट ने गडकरी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अंतरिम राहत की मांग पर जल्द सुनवाई करने का फैसला किया है.

मोदी ने स्काईरूट की सराहना की

विक्रम-1 की सफलता को बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली, 27 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की तेजी से बढ़ती उपलब्धियों की सराहना करते हुए स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक पवन चंदाना और नागा भरत डाका से हुई बातचीत को प्रेरणादायक बताया है.

सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों उद्यमियों के साथ उनकी बेहद सकारात्मक और उपयोगी चर्चा हुई, जिसमें स्काईरूट के विक्रम-1 मिशन की सफलता, कंपनी की अब तक की यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि पवन चंदाना और नागा भरत डाका का उत्साह, महत्वाकांक्षा और सकारात्मक सोच भारत के उभरते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है.

एके-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड

- सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई
- नोटिस भेजकर आपत्तिजनक कंटेंट हटवाए गए

सीवान, 27 जुलाई. बिहार के सीवान जिले में 25 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान एके -47 से फायरिंग करने वाले एसआईटी जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा के निर्देश पर फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस की डीप क्लीनिंग सोशल मीडिया से पीएम पर किए भद्दे पोस्ट, डिलीट कराए. जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर साझा किए गए भद्दे पोस्ट, फोटो और वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर आपत्तिजनक कंटेंट हटवाया गया है. पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे पोस्ट की पहचान कर रही है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. दरअसल, प्रदर्शन के दौरान कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों वाले वीडियो, भद्दी टिप्पणियां और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने ऐसे कंटेंट की पहचान के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी | सुको सख्त : सीए को शामिल करने के दिए निर्देश, , जांच में फॉरेंसिक ऑडिटर जोड़ने का सुझाव

दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे एसआईटी

नई दिल्ली, 27 जुलाई. राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दान राशि के दुरुपयोग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने सुझाव दिया कि जांच को अधिक निष्पक्ष, तकनीकी रूप से मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए एसआईटी में एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए.

राज्य सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच पूरी निष्पक्षता से आगे बढ़ेगी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीए को शामिल करने को निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत इस मामले को बंद नहीं कर रही है, बल्कि सुधारात्मक कदमों के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहती है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल पूरा ध्यान जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने पर है.

> वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अदालत में दलील दी कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए छोटे-बड़े दान की पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि लोगों को भरोसा रहे कि उनकी दी गई राशि ट्रस्ट तक पहुंची है. उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रस्ट को प्राप्त दान की जानकारी नियमित रूप से वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जा सकती है.

> **शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज नहीं कर सकते**
>
> मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण और न्यायसंगत प्रदर्शन संविधान के तहत सुरक्षित हैं और विरोध-प्रदर्शन लाठीचार्ज नहीं कर सकते है. उन्होंने ये मौखिक टिप्पणियां तब कीं जब बैंच आरोप लगाने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी.